

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 248)

पटना, बुधवार, 30 मार्च 2016

सं० 1प्रा0आ0-04/2010/1308/आ०प्र0 आपदा प्रबंधन विभाग

> संकल्प 29 मार्च 2016

विषय:—14वें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015—16 से 2019—20 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति के संबंध में।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 1940/आ0प्र0 दिनांक 06.08.2010 के माध्यम से राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी ।

- 2. 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015—16 से अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन किया जाना है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की जानी है।
- 3. केन्द्रीय गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्र सं0–33–5/2015–NDM-I, दि0–30 जुलाई, 2015 के माध्यम से प्राप्त 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) का निम्नवत् गठन किया जाता है :--
- 3.1 वित्तीय वर्ष 2015—16 से अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) का गठन किया जाता है। इस कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं यथा—चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू—स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटने, कीट आक्रमण, पाला (Frost) एवं शीतलहर से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्ति हेतु किया जाएगा।
- 3.2 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) में उपलब्ध राशि की 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने हेत् व्यय की जाएगी।
- 3.3 केन्द्रीय गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्र सं0 33—15 / 2015—NDM-I, दि0 17 अगस्त, 2015 के आलोक में राज्य आपदा रिस्पौंस कोष की वर्षवार कर्णांकित राशि का 5 प्रतिशत राशि क्षमता निर्माण से संबंधित कार्यों जिसमें आपातकालीन संचालन केन्द्रों (EOCs) की स्थापना / सुदृढ़ीकरण,सहभागियों एवं कर्मियों के

प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण, राज्य के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के आपदा प्रबंधन केन्द्रों को सहयोग प्रदान करने, राज्य / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA/DDMAs) का सुदृढ़ीकरण आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने आदि कार्य भी शामिल होंगे, हेत् व्यय किया जाएगा।

- 3.4 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) की राशि को "मुख्य बजट शीर्ष-8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–122–आपदा राहत निधि, उपशीर्ष–0001–राज्य आपदा रिस्पौंस कोष, समूह शीर्ष-प्राप्ति" के अन्तर्गत वर्गीकृत एवं लोक लेखा में रखा जायेगा।
- 3.5 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में दिनांक 31.03.2015 को उपलब्ध शेष जमा राषि (Closing Balance) दिनांक 01.04.2015 को राज्य आपदा रिस्पौंस कोष की प्रारम्भिक जमा राशि (Opening Balance) होगी।
- 3.6 गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-33-4/2015 -NDM-I दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में केन्द्र और बिहार सरकार का अंशदान 75:25 के अनुपात में रहेगा। केन्द्र से केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने के उपरांत उसमें देय अनुपातिक राज्यांश की राषि जोड कर राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में राशि जमा होगी। वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि का अंशदान निम्न प्रकार होगा:-

		(रााश रू० कराड़ म)		
क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1.	2015—16	351.75	117.25	469.00
2.	2016—17	369.00	123.00	492.00
3.	2017—18	387.75	129.25	517.00
4.	2018—19	407.25	135.75	543.00
5.	2019—20	427.50	142.50	570.00
योग		1943.25	647.75	2591.00

- 3.7 जहाँ तक प्राकृतिक आपदा के संबंध में व्यय करने का प्रश्न है, यह राज्य के मुख्य बजट शीर्ष ''2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत'' के विभिन्न उप मुख्य शीर्षों / लघ् / उपशीर्षों में उपबंधित राशि से की जायेगी। इस प्रकार किये गए व्यय से कितनी राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में सामंजित की जायेगी, इसका निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति तय करेगी। जितनी राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से . सामंजित की जायेगी, उतनी राशि ''मुख्य बजट शीर्ष–8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–122–आपदा राहत निधि, उपशीर्ष–0001–राज्य आपदा रिस्पौंस कोष, समूह शीर्ष–व्यय'' के अन्तर्गत डेबिट करते हुए मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-05- आपदा राहत निधि, लघुशीर्ष-901—घटायें —आपदा राहत निधि से पुरी की गई राशि कोष, उपशीर्ष—0001—आपदा राहत कोष में किये गए व्यय (घटायें) में क्रेडिट करनी होगी ।
- 3.8 भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि "मुख्य बजट शीर्ष– 8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उपमुख्य शीर्ष–००, लघुशीर्ष–122–आपदा राहत निधि, उपशीर्ष–०००1–राज्य आपदा रिस्पींस कोष, समूह शीर्ष-प्राप्ति'' में स्थानान्तरित की जायेगी एवं इस राशि के संबंध में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं एवं केन्द्र सरकार के अनुदेशों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित होगी।
- 4. राज्य कार्यकारिणी समिति आपदा राहत/साहाय्य हेतु वित्तीय सहायता संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेगी। समिति राहत व्यय के वित्त पोषण से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेगी। समिति राज्य सरकार एवं भारत सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी, कोष का संचालन एवं प्रशासन करेगी तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार संग्रहणों (कोष में जमा राशि) का निवेश करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (एस०डी०आर०एफ०) से आहरित धन राशि वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिये जिनके लिये कोष का गठन किया गया है, और केवल गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्ग निर्देशों में सन्निहित व्यय मदों और मानदण्डों के अनुसार प्रयुक्त की जा रही है। समिति की बैठक अध्यक्ष के आदेशानुसार आयोजित की जायेगी।
- 5. राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का प्रशासन एवं संचालन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 (i) (ii) के अनुसार राज्य सरकार के ज्ञापांक 1597 दिनांक 25.6.08 द्वारा गठित राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा। उक्त राज्य कार्यकारिणी समिति निम्न रूपेण गठित है:-
 - 1. मुख्य सचिव- अध्यक्ष
 - 2. विकास आयुक्त- सदस्य
 - 3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग- सदस्य
 - 4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग- सदस्य
 - 5. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग- सदस्य (समिति के संयोजक)

इस समिति को सचिवीय सहायता आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय सचिवों को, जो साहाय्य कार्य में सम्बद्ध होंगे, समय-समय पर आमंत्रित कर सकेगी। समिति की महत्ता को देखते हुए अन्यथा परिस्थितियों को छोड़ कर बैठक में आमंत्रित प्रधान सचिव/सचिव स्वयं भाग लेंगे। जब कभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को भाग लेना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो, वहाँ ही अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे।

- 5. 13वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति पर राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में बची राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में अन्तरित मानी जाएगी।
 - 6. इस संकल्प में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा संकल्प की प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, व्यास जी, सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 248-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in